

मंगलवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत प्र.मंत्री मोदी से मिले थे

इस मीटिंग का ही नतीजा माना जा रहा है, “जातिगत जनगणना” (कास्ट सैंसस) पर सरकार का निर्णय

-रेपु मित्र-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 अप्रैल एलओसी के उस पार बम गिराने के बजाय, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जातिगत जनगणना की घोषणा करके एक दूसरा विस्कोट किया है। यहाँ गांधी बाबर इसकी मोहन कर रहे थे और अपने इस एंडो पर बड़े प्रश्न, निष्ठा एवं नियमितता के साथ जोर देते आ रहे थे।

संसद में बोलते हुए, राहुल गांधी ने कहा था कि जातिगत जनगणना की घोषणा करने के लिए नरेन्द्र मोदी की सरकार को बाध्य करेंगे।

यह स्पष्ट नहीं है कि मोदी एंड कम्पनी का यह हृदय -परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ, क्योंकि प्रधान और सरकार जातिगत जनगणना का निरंतर विरोध करती आ रही थी, क्योंकि इसे हिन्दू-मुस्लिमों को बाँटें वाला उनका एंडो कमज़ोर होता है।

कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की थी, तथा जातिगत जनगणना के इस निर्णय को इन दोनों की कल की मीटिंग के नतीजे के रूप में देखा जा रहा है।

पिछले वर्ष केरल में ही कार्यकारिणी की तीन दिन की मीटिंग के बाद, आरएसएस ने यह ‘ऑन रिकॉर्ड’ कहा था कि वह जातिगत जनगणना के

- जैसा कि विदित ही है, गत वर्ष, केरल में हुई आरएसएस कार्यकारिणी की बैठक में, अधिकृत रूप से निर्णय लिया गया था कि संघ, “जातिगत जनगणना” के पक्ष में रहेगा।
- राहुल गांधी ने जाति “जनगणना” के पक्ष में सरकार का मन बदलवाने का श्रेय न लेकर कहा कि “जातिगत जनगणना” की प्रक्रिया का मॉडल तेलंगाना का मॉडल हो, न कि “जातिगत जनगणना” का बिहार मॉडल, जिससे सही सवाल, सही तरीके से पूछे जायेंगे तथा जातिगत गणना का पूरा लाभ मिलेगा जनता को।
- राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बढ़ायित न हो।
- राहुल गांधी ने कहा, प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में भी 15 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान अनिवार्य रूप से लागू हो। हालांकि, इसे संवैधानिक अधिकार माना गया है, पर, उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है।
- राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उह इस बारे में कोई स्थिर नहीं है कि जातिगत जनगणना का निर्णय अचानक क्यों लिया गया है, पर, केवल यह खुशी है कि यह निर्णय लिया गया है।

बाद, आरएसएस ने यह ‘ऑन रिकॉर्ड’ कहा था कि वह जातिगत जनगणना के

पक्ष में है।

जो भी हो, इस निर्णय का समय अपने आप में बड़ा रुचिकर है। यह एक ऐसा समय है, जब पूरा देश सरकार से यह अपेक्षा कर रहा है कि सरकार पहलाना में हुई निर्देश नामांकनों की हत्या की प्रतिक्रिया के बिकलान के खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही करेगी।

राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ शब्दों में प्रधानमंत्री के कार्यवाही करें, बिल्कुल भी हिंदू-सुरक्षित रखा जाए जिससे युवा युवती भी महाराष्ट्र के मंजूरी मार्डंडों की पालना करवाते हुए, धूम का भविष्य में डॉर्नए जांच के लिए सुरक्षित रखा जाए। यह जातिगत गणना का पूरा लाभ मिलेगा जनता को।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास

प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बढ़ायित न हो।

राहुल गांधी ने कहा, प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में भी 15 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान अनिवार्य रूप से लागू हो। हालांकि, इसे संवैधानिक अधिकार माना गया है, पर, उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उह इस बारे में कोई स्थिर नहीं है कि जातिगत जनगणना का निर्णय अचानक क्यों लिया गया है, पर, केवल यह खुशी है कि यह निर्णय लिया गया है।

पिछले वर्ष केरल में ही कार्यकारिणी की तीन दिन की मीटिंग के

पक्ष में है।

जो भी हो, इस निर्णय का समय अपने आप में बड़ा रुचिकर है। यह एक ऐसा समय है, जब पूरा देश सरकार से यह अपेक्षा कर रहा है कि सरकार पहलाना में हुई निर्देश नामांकनों की हत्या की प्रतिक्रिया के बिकलान के खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही करेगी।

राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ शब्दों में प्रधानमंत्री के कार्यवाही करें, बिल्कुल भी हिंदू-सुरक्षित रखा जाए जिससे युवा युवती भी महाराष्ट्र के मंजूरी मार्डंडों की पालना करवाते हुए, धूम का भविष्य में डॉर्नए जांच के लिए सुरक्षित रखा जाए। यह जातिगत गणना का पूरा लाभ मिलेगा जनता को।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास

प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बढ़ायित न हो।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास

प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बढ़ायित न हो।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास

प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बढ़ायित न हो।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास

प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बढ़ायित न हो।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास

प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बढ़ायित न हो।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास

प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बढ़ायित न हो।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास

प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बढ़ायित न हो।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास

प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बढ़ायित न हो।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास

प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बढ़ायित न हो।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास

प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बढ़ायित न हो।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास

प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बढ़ायित न हो।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास

प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बढ़ायित न हो।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास

प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बढ़ायित न हो।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास

प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बढ़ायित न हो।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास

प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बढ़ायित न हो।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास

प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बढ़ायित न हो।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास

प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बढ़ायित न हो।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास

प्रतिशत की सीमा भी हटायी ज

